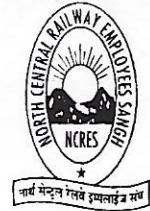




# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 85 /NCRES/20

Date : 9.5.2020

श्रीमान डा० एम. राघवैय्या जी  
महामंत्री—एन.एफ.आई.आर.  
नई दिल्ली।

विषय :— खर्च में कटौती करने हेतु पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जारी पत्र पर NCRES  
की मद वार टिप्पणी।

संदर्भ :— आपका पत्र II/80(i)/2019-Pt.I दिनांक 24.4.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा व्यय नियंत्रण के प्रस्ताव पर NCRES की मद वार टिप्पणी निम्न है –

(1) स्वच्छ रेल यात्रा एवं स्वच्छ स्टेशन का दायित्व को पहले ही On Board House Keeping Scheme (OBHS) एवं Clean Train System (CTS) के तहत आउटसोर्स कर दिया गया है जिसका अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम देखने का नहीं मिला है। NCRES का सुझाव है कि रेलवे स्वच्छता के मद में 50% से ज्यादा आउटसोर्सिंग न की जाय एवं स्वच्छ स्टेशन एवं स्वच्छ ट्रेन के मामले में कोई समझौता न किया जाय।

(2) “कू” के उचित विश्राम एवं सुविधाओं से कोई समझौता न करते हुये उचित उपयोगिता के लिये कार्य प्रणाली का पुनर्वलोकन किया जा सकता है।

(3) गार्डों के लिये जरूरी समस्त संरक्षा एवं सुरक्षा सम्बन्धित उपकरण हल्के बैगो में रखना सम्भव / सुरक्षित नहीं है।

(4) सहमत

(5) RPF को जुर्माना – कलेक्शन का अधिकार दे कर उनको उनके मुख्य कार्य से विमुख करना है एवं साथ ही यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कदम होगा।

(6) टिकट चेकिंग कैडर की रिकितयों को भरा जाय और पिछले 10 वर्षों में चलायी गई नई गाड़ियों के अनुसार पदों का सृजन किया जाय। टिकट चेकिंग का अधिकार अन्य विभागों के स्टाफ को देने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नया जोन बनने से पहले प्रयागराज मण्डल में ईंजी. एवं अन्य विभाग के सरप्लस स्टाफ को टिकट चेकिंग के कार्य में लगाया गया था लेकिन भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा शिकायतें मिलने पर इस स्कीम को बन्द कर दिया गया था।

(7) जाब एनालिसिस नार्मस को यदि रिव्यू करना है तो उसका उद्देश्य मात्र कर्मचारी/पदों को अव्यवहारिक रूप में कम करना ही नहीं होना चाहिये बल्कि नई गाड़ियों के बढ़े संचालन एवं कार्य को देखते हुये पदों को बढ़ाना होना चाहिये।

(8) सहमत

(9) सहमत

(10) सहमत

(11) सहमत

(12) परन्तु कर्मचारी हित के कार्य करवाये जाने चाहिये।

(13) कर्मचारी हित में कोई कटौती नहीं होना चाहिये।

(14) सहमत

(15) सहमत

(16) प्रशासनिक कार्य से बाहर जाने पर कर्मचारी TA क्लेम करते हैं। 50% TA कम करने के लिये कर्मचारी के ड्यूटी रोस्टर एवं निरीक्षण शेड्यूल को रिव्यू करे।

(17) ओवर टाइम की जगह CR दिया जाय।

(18) Covid - 19 के नाम पर कर्मचारी हित के कार्यों की अवहेलना न की जाय बल्कि प्रशासनिक खर्च में कमी लाई जाय।

(19) सहमत

(20) LHB अथवा Non LHB कोचों का अनुरक्षण संरक्षा से जुड़ा मुद्दा है एवं अभी Non LHB कोचों की ही संख्या अधिक है। अतः अभी इस पर निर्णय लेना जल्दबाजी होगी।

(21) सहमत

(22) सहमत

(23) संरक्षा को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जाय।

(24) यह उचित नहीं होगा क्योंकि State Electricity Board रेलवे को सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर देता है एवं सीधे सप्लाई लेने पर कटौती के कारण जनरेटर आदि का खर्च बढ़ेगा एवं आवश्यक सेवाओं हेतु सप्लाई निर्बाध रूप से नहीं मिल पायेगी।

(25) सहमत

(26) सहमत

(27) आवश्यकता अनुसार निर्णय किया जाय।

(28) सहमत

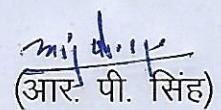
(29) हबीबगंज स्टेशन का रेट सभी स्टेशनों के लिये निर्धारित नहीं किया जा सकता। स्थानीय स्थिति के अनुसार पार्किंग रेट निर्धारित किया जाना चाहिये।

(30) Man/Material हेतु व्हीकल बंद करने से Transportation खर्च बढ़ जायेगा परन्तु इसकी भरपाई प्रत्येक अधिकारी को व्हीकल देने के बजाय पूलिंग बेस पर 10 अधिकारियों पर एक व्हीकल दिये जाय।

(31) कर्मचारी हित हेतु मीटिंग जारी रखी जाय। SBF से संचालित गतिविधियों पर रोक न हो।

(32) कोविड-2019 के नाम पर कर्मचारी हित की आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च की पूर्ति करने में कोई कटौती न की जाय।

(33) पुनर्विचार किया जाय।

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री